†राष्ट्र भाषा सलाहकार समिति

1262. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्र भाषा सलाहकार समिति के कौन-कौन सदस्य हैं, कब इसकी स्थापना हुई, समिति की कितनी बैठकें हो चुकी हैं और इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

‡[NATIONAL LANGUAGE ADVISORY COMMITTEE

1262. SHRI J. P. YADAV : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state the composition of the National Language Advisory Committee, when was it constituted, how many meetings of the Committee have been held and what progress has so far been made in this connection?]

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : राष्ट्र भाषा सलाहकार समिति नामक कोई समिति नहीं है । परन्तु केन्द्रीय हिन्दी समिति है, जिसकी अध्यक्षा प्रधान मंत्री हैं । इस समिति के सदस्यों के नाम संलग्न विवरण I में दिए गए हैं। यह समिति 5 सितम्बर, 1967 को गठित हुई थी । इसकी अब तक तीन बैठकें हुई हैं ।

समिति द्वारा दिये गये मुख्य-मुख्य निर्णय तथा उनपर की गई कार्रवाई का एक विवरण II संलग्न है ।

विवरण I

(1) श्रीमती इन्दिरा गांधी, प्रधान मंत्री—अध्यक्ष ।

(2) श्री मोरारजी देसाई, उप प्रधानमंत्री—सदस्य ।

(3) श्री यशवन्तराव चव्हाण, गृह मंत्री—सदस्य ।

(4) श्री त्रिगुण सेन, शिक्षा मंत्री—सदस्य ।

(5) श्री के० के० शाह, सूचना व प्रसारण मंत्री—सदस्य ।

(6) श्री पी० गोविन्द मेनन, विधि मंत्री—सदस्य ।

(7) श्री गंगा शरण सिंह, संसद् सदस्य—सदस्य ।

(8) श्री एम० एस० मूर्ति, संसद् सदस्य—सदस्य ।

(9) सेठ गोविन्द दास, संसद् सदस्य—सदस्य ।

(10) श्री प्रकाशवीर शास्त्री, संसद् सदस्य—सदस्य ।

(11) श्री उमाशंकर दीक्षित, संसद् सदस्य—सदस्य ।

(12) श्री नाथ पाई, संसद् सदस्य—सदस्य ।

(13) श्री रामधारी सिंह दिनकर, भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार—सदस्य-सचिव ।

विवरण II

1. हिन्दी सलाहकार की रिपोर्ट मे दिये गये सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए, तथा उनके कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों पर हिन्दी सलाहकार के साथ विचार-विमर्श किया जाना चाहिए ।

सम्बन्धित मंत्रालयों अर्थात् शिक्षा विधि, सूचना व प्रसारण तथा गृह मंत्रालय में कार्रवाई की जा चुकी है, अथवा की जा रही है ।

---

†Transferred from the 19th December, 1968.

‡[ ] English translation.

2. हिन्दी सलाहकार की अध्यक्षता में गृह, शिक्षा, विधि तथा सूचना व प्रसारण मंत्रालयों के संयुक्त सचिवों की एक समन्वय समिति गठित की जाए ।

इन मंत्रालयों के हिन्दी से संबंधित संयुक्त सचिवों की एक समन्वय समिति गठित की जा चुकी है। हाल ही में इस समिति में विदेश मंत्रालय, रेलवे बोर्ड तथा डाक व तार विभाग के प्रतिनिधि नामित किये गय हैं ।

3. हिन्दी के प्रसार, विकास तथा केन्द्र के सरकारी कामकाज के लिए इसके प्रगामी प्रयोग से सम्बन्धित सारी योजनाओं के सम्बन्ध में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को हिन्दी सलाहकार से परामर्श करना चाहिए ।

भारत सरकार सभी मंत्रालयों और विभागों का ध्यान इस निर्णय की ओर आकर्षित किया गया है ।

4. हिन्दी शिक्षण योजना की गति तेज करने के लिये गृह मंत्रालय द्वारा सुझाये गये उपायों के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करने के हेतु मंत्रि-मंडल सचिव सभी सचिवों की एक बैठक बुलाए और इस प्रकार विभागों को नये अनुदेश जारी किये जायें ।

हिन्दी शिक्षण योजना की गति तेज करने के लिए अनुमोदित उपायों के सम्बन्ध में अनुदेश जारी किये गये हैं ।

5. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 5(2) तुरंत लागू की जानी चाहिए ।

इस सम्बन्ध में विधि मंत्रालय के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

6. एल० एल० बी० स्तर तक कानून की पढ़ाई के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक पाठ्य-पुस्तकों का हिन्दी में प्रकाशन ।

इस निर्णय के कार्यान्वियन के लिए विधि मंत्रालय कार्रवाई कर रहा है ।

7. (क) सभी मंत्रालयों से यह कहा जाना चाहिए कि वे प्रेस सूचना ब्यूरो को अपनी प्रचार सामग्री हिन्दी तथा अंग्रेजी में साथ-साथ भेजे ।

सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों/विभागों को इस सम्बन्ध में अनुदेश जारी कर दिये हैं ।

(ख) प्रात: व शाम के मुख्य हिन्दी समाचार बुले-टिनें पहले प्रसारित की जायं और अंग्रेजी बुलेटिनें उसके बाद ।

यह निर्णय कार्यान्वित किया जा चुका है।

(ग) प्रेस सूचना ब्यूरो सारी प्रचार सामग्री हिन्दी और अंग्रजी दोनों भाषाओं में जारी करे ।

यथासम्भव ऐसा किया जा रहा है ।

8. हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन चलने वाली हिन्दी कक्षाओं में जाने के लिए प्रत्येक मंत्रालय से 20 प्रतिशत कर्मचारी भेजने की जिम्मेदारी प्रत्येक मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी को

भारत सरकार के प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में संयुक्त साचिव उसके समस्तर के एक वरिष्ठ अधिकारी को ये जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं ।

सौंपी जानी चाहिए और वह अधिकारी एक संयुक्त सचिव के स्तर का हो। उसी अधिकारी को हिन्दी के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये प्रशासनिक अनुदेशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी जाए।

9. हिन्दी के प्रसार और विकास तथा संघ के विभिन्न सरकारी कामकाज के लिए इसके प्रगामी प्रयोग की गति तेज करने के हेतु संसद द्वारा पारित सरकारी संकल्प के कार्यान्वयन के लिए कार्यक्रम तैयार किया जाए और उसे कार्यान्वित किया जाए।

सन् 1968-69 के दौरान कार्यान्वयन के लिए शिक्षा, विधि, सूचना व प्रसारण तथा गृह मंत्रालय ने विस्तृत कार्यक्रम तैयार कर लिए हैं।

10. विदेशों में हिन्दी के प्रचार से सम्बन्धित योजना को मंत्रिमंडल सचिव के परामर्श से कार्यान्वित किया जाए।

इस योजना को अंतिम रूप देने के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में अंतर-विभागीय समिति की एक बैठक हुई थी। उस बैठक में हुए निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए शिक्षा मंत्रालय तथा भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

†[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : There is no National Language Advisory Committee. There is, however, a Central Hindi Committee of which Prime Minister is the Chairman. Composition of the Committee is indicated in the attached statement I. The Committee was constituted on the 5th September, 1967. It has so far held three meetings.

A statement II showing important decisions of the Committee and action taken thereon is attached.

STATEMENT I

(1) Smt. Indira Gandhi, Prime Minister —*Chairman.*

(2) Shri Morarji Desai, Dy. Prime Minister—*Member.*

(3) Shri Y. B. Chavan, Home Minister—*Member.*

(4) Shri Triguna Sen, Education Minister—*Member.*

(5) Shri K. K. Shah, I. & B. Minister —*Member.*

(6) Shri P. Govinda Menon, Law Minister—*Member*

(7) Shri Ganga Sharan, M.P.—*Member.*

(8) Shri M. S. Murti, M.P.—*Member.*

(9) Seth Govind Das, M.P.—*Member.*

(10) Shri Prakash Vir Shastri, M.P.—*Member.*

(11) Shri Umashankar Dikshit, M.P.—*Member.*

(12) Shri Nath Pai, M.P.—*Member.*

(13) Shri R. D. Sinha Dinkar, Hindi Adviser to the Government of India—*Member-Secretary.*

†[ ] English translation.

STATEMENT II

1. Steps should be taken to implement the suggestions contained in the Hindi Adviser's report, and difficulties in their implementation should be discussed with the Hindi Advisor.	Action has already been taken or is in progress in the concerned Ministries, namely, Education, Law, Information and Boradcasting and Home Affairs.
2. A co-ordination Committee of the Joint Secretaries in the Ministries of Home Affairs, Education, Law and Information and Broadcasting be constituted under the chairmanship of the Hindi Adviser.	A Co-ordination Committee of Joint Secretaries dealing with Hindi in these Ministries has been constituted. Recently representatives of the Ministry of External Affairs, Railway Board and P&T Department have been nominated on the Committee.
3. All the Ministries and Departments of the Government of India should consult the Hindi Adviser in regard to all the schemes pertaining to the propagation, development and progressive use of Hindi for Official work of the Union.	This has been brought to the notice of all the Ministeries and Departments of the Government of India.
4. The Cabinet Secretary should call a meeting of all the Secretaries to discuss the measures suggested by the Home Ministry for accelerating the pace of the Hindi Teaching Scheme and accordingly fresh instructions be issued to the Departments.	Instructions containing the approved measures for accelerating the pace of Hindi Teaching Scheme have been issued.
5. Section 5(2) of the Official Languages Act, 1963 should be enforced immediately.	This is under consideration in consultation with the Ministry of Law.
6. The production of text-books in Hindi which are essentially required for teaching Law upto the L.L.B. standard should be taken up first.	Ministry of Law are taking steps to implement this decision.
7. (a) All the Ministries should be asked to send their publicity material to the Press Information Bureau in Hindi and English simultaneously.	Ministry of Information & Broadcasting has issued instructions to all the Ministries/Departments in this regard. The decision has been implemented.
(b) The morning and evening main Hindi News bulletins should be broadcast first and English bulletins later.	These two news bulletins are being relayed by all the stations of A.I.R. This is being done to the extent possible.
(c) The Press Information Bureau should issue all publicity material in both the languages, *i.e.* Hindi & English.	
8. The responsibility for releasing 20% of the employees in each Ministry for attending the Hindi classes conducted under the Hindi Teaching Scheme should be entrusted to a senior officer of each Ministry and that such officer should be of the status of a Joint Secretary. The same officer should be entrusted with the responsibility for ensuring the implementation of the administrative instructions issued from time to time regarding use of Hindi.	A senior officer of the rank of Joint Secretary/officer of equivalent rank has been given these responsibilities in each Ministry/Department of Government of India.

9. For implementation of the Government Resolution adopted by Parliament programmes should be prepared and implemented for accelerating the spread and development of Hindi and its progressive use for the various official purposes of the Union.	Detailed programmes have been prepared by the Ministries of Education, Law, Information and Broadcasting and Home Affairs for implementation during the year 1968-69.
10. The scheme of propagation of Hindi abroad should be translated into action in consultation with the Cabinet Secretary.	A meeting of the Inter-departmental Committee for finalising the scheme was held under the chairmanship of the Cabinet Secretary. Necessary action is being taken by the Ministry of Education and the Indian Council of Cultural Relations for implementing the decisions taken at the meeting.]

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

ALLEGED DISCRIMINATION AGAINST THE PEOPLE OF KERALA IN THE MATTER OF ISSUING POSSESSION LICENCES FOR WIRELESS TRANSMITTERS

SHRI K. P. SUBRAMANIA MENON (KERALA) : Sir, I call the attention of the Minister of Parlimentary Affairs and Communications to the recent circular addressed by the Director-General Posts and Telegraphs, New Delhi, to all Heads of Circles with regard to the issue of possession licences for wireless transmitters and the alleged discrimination against the people of Kerala thereby denying to the people of Kerala the same rights enjoyed by those in other States.

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND COMMUNICATIONS (SHRI I. K. GUJRAL) : Mr. Chairman, Sir, it had been observed that different procedures were being adopted by the P and T authorities in the different States for verifying the suitability of persons applying for issue of possession licences for wireless transmitters.

The matter was therefore examined and instructions were issued to the Heads of Circles to have a verification made through district authorities. As in the State of Kerala, the Chief Minister had written to the Home Minister earlier expressing his dissatisfaction with the criteria for verification of character and antecedents of candidates for Central Government employment and it had been found necessary to make some other arrangements for verification of character and antecedents of the candidates in the State of Kerala, it was thought that in this case also similar arrangements may be made till the issue is decided with the Kerala Government. The idea is only to verify the suitability of persons applying for licence for possession of wireless transmitters before a licence for the purpose is granted to them. There has, thus, been no discrimination against the people of Kerala in any manner.

SHRI K. P. SUBRAMANIA MENON: Sir, this matter of discrimination against Kerala people is practised in all respects In the case of police verification whereas in all other States it is the district authorities who conduct the police verification in the case of Kerala the Home Ministry is to specially conduct the verification. Similarly in regard to wireless licences also the same thing is being repeated. It would seem from the whole thing that the Kerala people are being denied the same status and the same rights as the people of other parts of India on political grounds.

SHRI M. RUTHNASWAMY (Madras): Special treatment.

SHRIMATI YASHODA REDDY (Andhra Pradesh) : Extra special.